

समाजवादी बुलेटिन

ट्रैक्टर रैली में गणतंत्र की झांकी 28 बजट 2021 : नाम बड़े और दर्शन छोटे 48

समाजवादी हैं तेयार

08



भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से है और सरकार उसे हल्के में न लें। चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं बन सकता। पाकिस्तान की तुलना में चीन ज्यादा बड़ा खतरा है। तिब्बत को सौंपना भारत की बड़ी भूल थी।

मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी



प्रिय पाठकों,
समाजवादी बुलेटिन
आपकी अपनी पत्रिका है।
इसके नए और बदले
कलेक्टर को आप सबने
सराहा है। आपका यह
उत्साह वर्धन हमारी ऊर्जा
है। कृपया अपनी राय से
हमें अवगत कराते रहें।
इसके लिए आप हमें नीचे
दिए गए ईमेल पर लिख
सकते हैं। कृपया अपना
पूरा नाम, पता एवं
मोबाइल नंबर जरूर दें।
हम बुलेटिन को और
बेहतर बनाने का प्रयास
जारी रखेंगे। आपके संदेश
की प्रतीक्षा रहेगी।
धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

✉ samajwadibulletin19@gmail.com

✉ bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

📌 /samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

आस्था प्रिंटेर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

किसान धोखे का जवाब वोट से देंगे



43

08 कवर स्टोरी

समाजवादी हैं तैयार



समाजवादियों की ट्रैक्टर रैली में गणतंत्र की झांकी

किसान आंदोलन

28



महापंचायतों में दिख रही अन्नदाता की ताकत
बजट 2021 : नाम बड़े और दर्शन छोटे

42

48

चा हे पेट्रोल-डीजल हो या फिर रसोई गैस- बढ़ती कीमत ने नरेंद्र मोदी सरकार को खुद अपने ही घोषित लक्ष्य और पैमानों पर निरुत्तर कर दिया है। कच्चे तेल का आयात कम करने, पेट्रोल-डीजल की खपत घटाकर सौर ऊर्जा समेत वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने और इस तरह डॉलर बचाने की नीति से खुद मोदी सरकार पलट गयी। अधिक खपत-अधिक मुनाफे वाली नयी नीति ने आत्मनिर्भरता के मंत्र की भी हवा निकाल दी। वहीं आम लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर को महंगा होने देना कबूल किया जबकि सब्सिडी के लिए आम बजट में आवंटित रकम पड़ी रह गयी। अगर इस रकम का इस्तेमाल किया जाता तो गैस सिलेंडर की कीमत को बढ़ने से रोका जा सकता था।

भुला दिया गया कच्चे तेल का आयात घटाने का लक्ष्य

2014-15 में जब भारत अपनी जरूरत का 77 फीसदी कच्चा तेल आयात कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया था कि वे 2022 तक आयात पर इस निर्भरता को 10 प्रतिशत तक घटा देंगे और इसे 67 फीसदी पर ले आएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सकारात्मक लक्ष्य था। मगर, व्यावहारिक मोर्चे पर यह लक्ष्य उल्टा हो गया। कच्चे तेल का आयात 10 प्रतिशत घटने के बजाए तकरीबन 7 प्रतिशत बढ़ गया। अब यह

मोदी राज में महंगाई बेकाबू



प्रेम कुमार
पत्रकार, लेखक



84 प्रतिशत के करीब वाले स्तर पर जा पहुंचा है।
ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत
जरूरी है।

जब मोदी सरकार ने कच्चे तेल के आयात को
घटाने का लक्ष्य तय किया था तो उसका मकसद
था कि विदेशी मुद्रा को बचाया जाए। इस सोच
को देश के लोग सलाम कर रहे थे क्योंकि इसी
विदेशी मुद्रा के संकट ने 1990 में तत्कालीन
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को सोना गिरवी रखने के
विवश कर दिया था। सोलर एनर्जी समेत
रेन्युएबल एनर्जी में आत्मनिर्भरता के मकसद से
जुड़कर इस लक्ष्य को पाया जा सकता था। इस
दिशा में पहल भी हुए। मगर, इस दौरान मोदी
सरकार का वह मकसद ही बदल गया कि आयात
पर निर्भरता घटाना है! कच्चे तेल के आयात बिल
की चिंता ही पीछे छूट गयी! क्यों?- क्योंकि मोदी
सरकार की आर्थिक जरूरतों का स्रोत बनकर
उभरने लगा कच्चा तेल।

आत्मनिर्भरता नहीं मुनाफा बन गयी मोदी सरकार की नीति

मोदी सरकार इस रास्ते पर चल पड़ी कि जितना
कच्चे तेल का आयात होगा, जितना अधिक
इसकी खपत होगी, मुनाफा उतना ज्यादा होगा।
यही कारण है कि कोरोना काल में जब देश में
कारोबार ठप थे, ट्रैफिक रुका हुआ था और
पेट्रोल-डीजल की मांग कम थी, तब भी पेट्रोल-
डीजल की कीमत का पहिया तेजी से घूम रहा
था। सिर्फ जून 2020 में 20 बार पेट्रोलियम
पदार्थों के दाम बढ़े हैं। कहने का अर्थ यह है कि
जैसे ही सरकार के पास पैसे कम पड़ने लगते हैं
तेल का दाम बढ़ा दिया जाता है।



कहां दिखा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य? : बढ़ता गया डॉलर में खर्च

2015-2016	73.92 अरब डॉलर
2016-2017	80.8 अरब डॉलर
2017-2018	101.44 अरब डॉलर
2018-2019	128.25 अरब डॉलर
2019-2020	119.06 अरब डॉलर
2020-2021 (अप्रैल-नवंबर)	40.30 अरब डॉलर

(स्रोत : पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल)

कहां दिखा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य? : नहीं थमी पेट्रो खपत

2015-2016	232.30 मिलियन मीट्रिक टन
2016-2017	250.21 मिलियन मीट्रिक टन
2017-2018	255.89 मिलियन मीट्रिक टन
2018-2019	259.84 मिलियन मीट्रिक टन
2019-2020	270.74 मिलियन मीट्रिक टन

2015 में कच्चे तेल के आयात पर करीब 64 अरब डॉलर हम खर्च कर रहे थे। 2019-20 में यह बढ़कर 119 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। पहले चिंता थी कि पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी तो कच्चे तेल का आयात बिल कम होगा। अब आयात बिल की चिंता नहीं रही। अब चिंता हो गयी कि पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी तो सरकार का मुनाफा घट जाएगा। भारत ने 2014-15 में 210.73 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया था। 2019-20 में यही आयात बढ़कर 270.74 मिलियन मिट्रिक टन हो गया। सिर्फ पांच साल में करीब 29 फीसदी खपत बढ़ गयी।

जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब अर्थव्यवस्था की चिंता थी, राजस्व घाटे की चिंता थी। अब, सिर्फ और सिर्फ राजस्व और वह भी मुनाफा आधारित राजस्व की चिंता प्रमुख हो गयी। कहने की जरूरत नहीं कि कच्चे तेल की नीति से जुड़ी आत्मनिर्भरता का सिद्धांत भी तेल लेने चला गया। पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने से जुड़ा कोई सैद्धांतिक अभियान भी अब नहीं दिखता। सोलर एनर्जी से चलने वाली कारों को जमीन पर लाने का मकसद भी दूर-दूर तक नहीं सुनाई पड़ता जिसका 2014-15 में बहुत शोर था!

मोदी राज में पेट्रोल की कीमत ने तोड़े रिकॉर्ड

नरेंद्र मोदी के राज में पेट्रोल की कीमत ने रिकॉर्ड बनाया है। बीते 10 साल के रिकॉर्ड को देखें तो 4 अक्टूबर 2018 को पेट्रोल की कीमत उच्चतम स्तर पर थी और यह 84.06 रुपये प्रति लीटर बिका था। 2020 में सबसे सस्ता पेट्रोल 69.63 रुपये प्रति लीटर था।

डीजल की कीमत पहले ही रिकॉर्ड बना चुकी है। एक समय ऐसा भी आया जब डीजल की कीमत ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया। जाहिर है कि सब्सिडी हटाने और टैक्स बढ़ाने की नीति का पूरा बोझ आम उपभोक्ताओं पर थोपा जा चुका है।

कोरोना काल में जब देश में कारोबार ठप थे, ट्रैफिक रुका हुआ था और पेट्रोल-डीजल की मांग कम थी, तब भी पेट्रोल-डीजल की कीमत का पहिया तेजी से घूम रहा था। सिर्फ जून 2020 में 20 बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही सरकार के पास पैसे कम पड़ने लगते हैं तेल का दाम बढ़ा दिया जाता है

अगर 2014 से तुलना करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भी मनमोहन सरकार में चढ़ती कीमत का असर जुलाई तक बरकरार था और यह 21 जुलाई को 77.18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। मगर, अक्टूबर आते-आते में इसमें बड़ी गिरावट आ चुकी थी। 15 अक्टूबर को 62.05 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था। मगर, 2020 में कच्चा तेल 50 डॉल प्रति

बैरल के स्तर पर यानी रुपये में प्रति लीटर खरीद 25 रुपये करीब होने के बावजूद भारतीय खुदरा बाजार में पेट्रोल साढ़े तीन गुणा अधिक कीमत पर 84 रुपये के स्तर पर कैसे बिक रहा है? - यह चिंताजनक सवाल है।

जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं पेट्रोल-डीजल?

बीते छह सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आधी से भी कम रह गयी है। मगर, भारत की जनता को रिकार्ड तोड़ कीमत पर पेट्रोल-डीजल खरीदने को विवश होना पड़ा है। मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार नहीं है। इसकी वजह साफ है कि इस वक्त जहां सरकार पेट्रोल की कीमत का 70 फीसदी हिस्सा टैक्स के तौर पर वसूल रही है, जीएसटी में यह सीमा अधिकतम 28 फीसदी तक सिमट जाएगी। जाहिर है कि वर्तमान में अगर पेट्रोल के मूल्य को 72 रुपये प्रति लीटर मानें तो इसमें 50 रुपये के करीब सरकार टैक्स वसूल रही है जो जीएसटी के दायरे में करीब 20 रुपये ही होगी। इस तरह आम लोगों को प्रति लीटर 30 रुपये का फायदा होगा।

अभी और महंगी होगी रसोई गैस

2020 की शुरुआत रसोई गैस के दाम बढ़ने से हुई थी जब 1 जनवरी को रसोई गैस सिलेंडर 19 रुपये महंगा हो गया था। साल 2020 को अलविदा कहते हुए दिसंबर महीने में 50-50 रुपये प्रति सिलेंडर और फिर 10 जनवरी 2021 तक इसमें 50 रुपये की और अधिक वृद्धि के बाद उपभोक्ताओं के लिए इसे कुल डेढ़ सौ रुपये प्रति सिलेंडर महंगा कर दिया गया है।

21 जनवरी को दिल्ली में एलपीजी गैस की कीमत 52.52 रुपये प्रति किलो है। अगर एक सिलेंडर में 14.2 किय्रा गैस होती है तो एक सिलेंडर की कीमत इस हिसाब से 745.78 पैसे हुई।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ठंड के मौसम में खपत में बढ़ोतरी और इस वजह से मांग में वृद्धि को मूल्य वृद्धि की वास्तविक वजह बताया है। 1 मार्च 2020 को भी पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि मार्च से दाम घटने की संभावना है।

छह महीने में दुगुनी हुई गैस सिलिंडर की कीमत

अगस्त 2019 से 2020 के फरवरी के अंत तक यानी 6 महीने तक रसोई गैस के दाम बढ़ते ही चले गये और इस दौरान कीमत दुगुनी हो गयी। 12 फरवरी 2020 आते-आते रसोई गैस की कीमत 858.50 रुपये हो चुकी थी। ठंड में खपत बढ़ने की थ्योरी यहां नहीं दिखी।

1 मार्च 2020 को छह महीने में पहली बार रसोई गैस की कीमत घटी थी। वहीं 2020 में 3 और 15 दिसंबर को 50-50 रुपये प्रतिलीटर का

बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से दाम 100 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गये। दिल्ली में इसकी कीमत 594 से 694 तक पहुंच गयी। 6 फरवरी आते-आते एक सिलेंडर 719 रुपये में बिकता दिखा।



महंगाई के पीछे बढ़ती मांग सिर्फ बहाना है, मकसद सब्सिडी हड़प कर जाना है

प्रश्न यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो रसोई गैस की कीमत लगातार क्यों बढ़ती रही है? अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के हिसाब से मांग में बढ़ोतरी ही इसकी वजह है तो इसका मतलब यह है कि सरकार मांग बढ़ने से बढ़ने वाली सब्सिडी को लेकर चिंतित है। कीमत में बढ़ोतरी की वजह यही हो सकती है।

2019 के जून के महीने में रसोई गैस की कीमत 497 रुपये थी। तब ग्राहकों को 240 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी। जब 12 फरवरी 2020

को रसोई गैस की अधिकतम कीमत थी 858.50 रुपये, तब यह सब्सिडी नगण्य हो चुकी थी लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया। अब भी यह साफ नहीं किया गया है कि दिसंबर या

जनवरी में रसोई गैस खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगी या नहीं, जबकि सिलेंडर की ताजा कीमत 745.50 रुपये हो चुकी है।

अहम बात यह है कि वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी के मद में सरकार ने 40,915 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इनमें एलपीजी सिलेंडर के लिए

37,256.21 करोड़ रुपये थे। मगर, पहली तिमाही तक महज 1900 करोड़ रुपये ही इस मद में खर्च किए गये थे।

अगर सरकार ने सब्सिडी को बरकरार रखा होता तो रसोई गैस की बढ़ती कीमत को थामा जा सकता था। मगर, सरकार ने मांग बढ़ने के बहाने कीमत बढ़ाई और सब्सिडी मद के कोष बचा लिए। यह आम लोगों के साथ धोखाधड़ी है। मगर, पेट्रोलियम मंत्री इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

फोटो सौजन्य - गूगल



समाजवादी हैं तैयार





दुष्यंत कबीर

ह वा बसंती है और माहौल में नएपन का अहसास। ऋतु का यह बदलाव उत्तर प्रदेश में बड़े परिवर्तन की आहट भी संग लेकर आया है। संघर्षों और बलिदानों की गौरवशाली परंपरा के वाहक समाजवादी कार्यकर्ता इस बदलाव के अगुवा बनने के लिए तैयार हैं।

उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में मिशन 2022 के लिए

समाजवादी तैयार हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर हो रहे समाजवादी प्रशिक्षण शिविरों में समाजवादी आंदोलन के मूल्यों की व्याख्या के साथ चुनावी तैयारियों पर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

इन शिविरों में अपनी बात रखने लखनऊ से संबंधित स्थानों को जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की यात्रा के रास्ते में एवं दौरे के स्थान पर उनसे मिलने, देखने, सुनने के लिए जुट रही भारी भीड़ बता रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है।

माहौल में बदलाव की इस बयार और इसके लिए तैयार समाजवादियों के उत्साह की बानगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए नारे -

**नई हवा है, नई सपा है
बड़ों का हाथ, युवा का साथ**

में भी बखूबी झलकती है।

एक ओर संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद के तहत प्रशिक्षण शिविरों के अलावा पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर लगातार हो रही बैठकें, 2022 के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने की प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे जाने, सड़क पर उतर कर किसान घेरा, युवा घेरा, महिला घेरा और ट्रैक्टर रैली जैसे अनोखे तरीकों से सत्ता के अहंकार को चुनौती देने के कार्यक्रम, विभिन्न दलों के नेताओं के लगातार अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जैसे वाकए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने फिर एकबार समाजवादी सरकार बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं।

किसान आंदोलन के समर्थन में भी समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों के





गणतंत्र दिवस महाघोषणा

आज हमारे देश में संविधान, गणतंत्र-लोकतंत्र, आज़ादी सब ख़तरे में है, इसीलिए इस गणतंत्र दिवस पर सपा नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए, नये संकल्प लेकर, एक नयी घोषणा करने जा रही है:

**नयी हवा है ~ नयी सपा है
बड़ों का हाथ, युवा का साथ**

हमारा देश इसीलिए महान देश रहा है क्योंकि हमारे देश ने दुनिया को सदैव प्रेम एवं शांति का संदेश दिया है. आज यही संदेश हमें अपने देश-प्रदेश के अंदर देने की आवश्यकता आन पड़ी है. आइए घृणा और अविश्वास के स्थान पर मिल-जुलकर परस्पर प्रेम और आपसी-विश्वास से समाज, प्रदेश और देश को मज़बूत करें!

‘विकास सच्चा और काम अच्छा’ हमारा प्रेरणावाक्य है एवं ‘शांति और सौहार्द’ हमारा मूलमंत्र. हम सब जानते हैं एकता के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना विकास नहीं होता. इसलिए आइए हम सब, हर बहकावे-भटकावे से बचकर एकजुट होकर आगे बढ़ें और अमन-चैन के लिए हर संभव कोशिश करें!

जन-जन से मेरी अपील है, आइए सपा की ‘सपा का काम, जनता के नाम’ की जनहितकारी नीतियों से जुड़िए और एक नये उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए एक नया संकल्प धारण कीजिए!

आपका अखिलेश





हितों पर नजर रखने के लिए विशेष रूप से समाजवादी किसान समिति का गठन किया है। किसानों की महापंचायत के समर्थन में भी समाजवादी निरंतर सक्रिय हैं। गन्ना किसानों की मांगों को लेकर पार्टी ने खास सक्रियता दिखाई है और इन किसानों की समस्याओं को लगातार जोर शोर से उठाया है। संगठन और सड़क पर अपनी सक्रियता को लगातार साबित कर रही समाजवादी पार्टी ने शह और मात कि राजनीतिक खेल में भी विरोधियों को तब जबरदस्त मात दी जब हाल में हुए विधान परिषद के चुनाव में पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध जितवा लिया।



बुलेटिन ब्यूरो

को

ई नेता नहीं सब
कार्यकर्ता!

इसी मंत्र के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पार्टी की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में

समर्पित कार्यकर्ताओं की नई पौध को समाजवादी विचारों से लैस करने का काम सफलतापूर्वक जारी है। इस पहल से पार्टी में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।

बिठूर से शुरू हुआ प्रशिक्षण शिविरों का यह सिलसिला चितकूट, कानपुर, श्रावस्ती, बरेली और फर्रुखाबाद तक पहुंच चुका है। इनमें



समाजवादी आंदोलन का इतिहास प्रशिक्षण की महत्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से समाजवादी विचारों की जानकारी देने की समृद्ध परंपरा से भरा पड़ा है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उसी परंपरा को नए कलेवर के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है

चित्तकूट, श्रावस्ती, बरेली और फर्रुखाबाद के शिविरों को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया और इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि कोई नेता नहीं है, सबको कार्यकर्ता बनना है। अभी ऐसे कई और प्रशिक्षण शिविर अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।

समाजवादी आंदोलन का इतिहास प्रशिक्षण की महत्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से समाजवादी विचारों की जानकारी देने की

समृद्ध परंपरा से भरा पड़ा है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उसी परंपरा को नए कलेवर के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्राउड यानी भीड़ को कैडर में बदलना है। अखिलेश जी का स्पष्ट मानना है कि पार्टी के कार्यक्रमों या स्वयं उनके कार्यक्रमों में जो जबरदस्त भीड़ उमड़ती है उसे महज भीड़ ही न रहने दिया जाए बल्कि पार्टी के विचारों से जोड़ा जाए। ताकि नई पौध समाजवादी पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों से अवगत हो सके।

नई पौध को यह बताया जाए कि समाजवादी आंदोलन की संघर्ष की कितनी शानदार परंपरा रही है। साथ ही उन्हें मौजूदा राजनीति की हकीकत, खास तौर पर भाजपा की चालबाजी भरी, छिपे हुए चेहरे वाली एवं कथनी और करनी में अंतर वाली राजनीति से भी अवगत कराना है।

प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा ले रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ जुट जाना क्यों



समाजवादी क
प्रशिक्षण

स्थान
दिन

महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण शिविर में इस बात का विशेष उल्लेख किया जा रहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी खुद की पोलिंग बूथ पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में 90 फ़ीसदी तक मतदान करवाना क्यों जरूरी है।

प्रशिक्षण शिविरों में पार्टी की ओर से निर्धारित वक्ता यह बता रहे हैं कि क्यों जोड़ने का काम

जरूरी है न कि घटाने का। यह भी बताया जा रहा है कि अम लोगों से पूरी विनम्रता के साथ मिलने के कितने फायदे होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है कि कैसे गड्डू पाटने के लिए ऊंचे टीले से ही मिट्टी लानी पड़ती है। वैसे ही जो समर्थक किन्हीं वजहों से साथ छोड़ कर किसी और के साथ चले गए हैं, उन्हें गड्डू पाटने की तर्ज पर उनके पास जाकर ही उन्हें वापस अपने साथ







लाने का प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए राजनीति जोड़ने का काम है।

प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ समाजवादी, समाज के प्रबुद्ध तबके के लोग एवं समाजवादी चिंतक वक्ता के रूप में प्रशिक्षुओं को बता रहे हैं कि कैसे अयोध्या से जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले तो पूरे रास्ते लोगों को जोड़ते ही चले और इसी जोड़ने के कारण उन्होंने रावण को परास्त किया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल कार्यकर्ताओं को वक्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि राजनीति में सब को जोड़ना होगा, विनम्रता के साथ जोड़ना होगा।

शिविर में वक्ताओं द्वारा प्रशिक्षुओं को

जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले तो पूरे रास्ते लोगों को जोड़ते ही चले और इसी जोड़ने के कारण उन्होंने रावण को परास्त किया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल कार्यकर्ताओं को वक्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि राजनीति में सब को जोड़ना होगा, विनम्रता के साथ जोड़ना होगा

समाजवादी इतिहास की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे पार्टी के संस्थापक-संरक्षक नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पार्टी को कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस मुकाम तक पहुंचाया है।

इन प्रशिक्षण शिविरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें बगैर किसी तामझाम के, बेहद सादगी के साथ अायोजित किया जा रहा है। संबंधित मंडल की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन सौ की संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता शिविर में शामिल हो रहे हैं। तीन दिवसीय इन प्रशिक्षण शिविरों के समापन दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का संबोधन होता है। चूंकि वे समापन दिवस से पहले वाली शाम ही पहुंच कर





रात्रि निवास वहीं करते हैं लिहाजा स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपने नेता से मिलने का अवसर भी मिल जाता है। यह नेता से कार्यकर्ताओं के सीधे जुड़ाव की समाजवादी परंपरा का ही हिस्सा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच वयोवृद्ध समाजवादी नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है।





सबको भा रहा सपा का साथ

बुलेटिन ब्यूरो

वि

धानसभा चुनाव 2022 जैसे - जैसे करीब आ रहा है विभिन्न दलों के प्रमुख

नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समाजवादियों की सरकार बनाने का सिलसिला भी लगातार तेज होता जा रहा है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों पर आस्था जताते हुए 16 जनवरी 2021 को सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज

पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के प्रमुख नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

श्री अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि इन साथियों के आने से समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और सन् 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है।

सपा है बाबा साहब व डॉ लोहिया के विचारों की वाहक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा डॉ भीमराव अम्बेडकर और डॉ राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चल रही है। समाजवादी पार्टी समाजवादी व्यवस्था का राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं के सपा में शामिल होने के अवसर पर प्रेस कांफ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा षडयंत्रकारी जातिवादी पार्टी है। उसका काम नफरत फैलाना है। किसानों को लूटा जा रहा है। गलत नीतियों से नौजवानों का रोजगार छिना है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। यह भी जाने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। भाजपा समाज को बांटने का पाप कर रही है।

समाजवादी पार्टी गैर बराबरी, भेदभाव और नफरत को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही है।



समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में प्रमुख रहे, मेरठ की मेयर श्रीमती सुनीता वर्मा, हस्तिनापुर मेरठ के पूर्व विधायक श्री योगेश वर्मा, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद के पूर्व विधायक श्री विजय यादव, लखीमपुर के पूर्व सांसद श्री दाऊद अहमद और शाहजहांपुर के पूर्व मंत्री श्री अवधेश वर्मा, बरेली के पूर्व विधायक श्री विजय पाल सिंह, अलीगढ़ की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी धनगर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए हैं जबकि मिर्जापुर के पूर्व विधायक श्री राम भारतीय तथा गोरखपुर के आर.एस.एस. प्रचारक डॉ विनीत शुक्ला भाजपा से संबद्ध रहे हैं। इनके अलावा कई

डाक्टर तथा एडवोकेट भी समाजवादी पार्टी के सदस्य बने।

समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में सर्वश्री रमेश पाण्डेय जहूराबाद गाजीपुर, संदीप वर्मा एडवोकेट, इलाहाबाद, सुनील लोधी एडवोकेट पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग, डॉ अफरोज इरा अस्पताल, कृष्ण चंद्र मौर्य मिर्जापुर, राजेश कुमारी, कोरी संदीप वर्मा एडवोकेट आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

श्रीमती सुनीता वर्मा के साथ लगभग 2 दर्जन पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, बहुजन समाज पार्टी की जिला कार्यकारिण के

वरिष्ठ सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।

श्रीमती लक्ष्मी धनगर के साथ प्रधान, पूर्व प्रधान कोरी संदीप वर्मा एडवोकेट के साथ राष्ट्रीय कोरी-कोली समाज परिवर्तन संस्थान के तमाम पदाधिकारी, श्री अवधेश वर्मा के साथ कई जिला पंचायत सदस्य, एवं श्री विजय यादव के साथ तमाम ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं।





सपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध उच्च सदन पहुंचे

बुलेटिन ब्यूरो

स माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सटीक रणनीति से पार्टी के दोनों प्रत्याशी श्री अहमद हसन एवं श्री राजेन्द्र चौधरी विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए।



विधान परिषद की बारह सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी संख्या बल के आधार पर एक ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करवा पाती, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की सटीक रणनीति ने पार्टी के खाते में एक की बजाय उच्च सदन की दो सीटें डाल दीं। एक की जगह दो

प्रत्याशी घोषित कर एवं दोनों का नामांकन खुद करवाने के लिए पहुंचकर श्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा के दोनों प्रत्याशी श्री अहमद हसन व श्री राजेन्द्र चौधरी जीत कर विधान परिषद पहुंचेंगे।

उनकी इस रणनीति और आत्मविश्वास से सकते में आयी सत्तारूढ़ भाजपा व अन्य पार्टियों ने अतिरिक्त प्रत्याशी देने से ही गुरेज किया। एक निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। नतीजतन निर्विरोध निर्वाचन में सपा के दोनों उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

विधान परिषद के सदस्य की शपथ लेने के बाद सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी ने विधान भवन के सेन्ट्रल हाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन, विधान सभा में नेता विरोधी दल श्री रामगोविन्द चौधरी, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल सहित सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि वे सत्यनिष्ठा के साथ भारतीय संविधान के मूल्यों का निर्वहन करेंगे। बतौर सदस्य हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जनता की बात सदन तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाती है। आज सत्ताधारी दल लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। भाजपा का इरादा संवैधानिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने का है। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी बहुमत में है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। भाजपा से सामाजिक सद्भाव को खतरा है। उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार में ही संभव है।

आजम साहब की रिहाई की मांग तेज



बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के रामपुर दौरे के बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई की मांग लगातार तेज हो रही है। उन्हें कई मामलों में अदालत से जमानत भी मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार कानूनी मोर्चे पर सक्रिय है ताकि उन्हें बाकी मामलों में भी जमानत मिल सके और उनकी रिहाई हो सके।

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

22 जनवरी 2021 को रामपुर में श्री आजम खान के घर जाकर उनकी पत्नी एवं रामपुर की विधायक डॉ. तज़ीन फ़ातिमा व परिवार के अन्य सदस्यों से मिले थे। उन्होंने तज़ीन फ़ातिमा जी के साथ करीब डेढ़ घंटे बात की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे से रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की हौसलाअफजाई भी हुई। वे उत्साहित हैं और आजम खान साहब की रिहाई के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से आवाज बुलंद कर रहे हैं।

रामपुर के समाजवादियों व कानून पसंद



नागरिकों को इसपर भी हैरानी है कि जिस अधिकारी द्वारा आजम खान साहब पर मनमाने तरीके से मुकदमे लादे गए उसे केन्द्र व यूपी की सरकार ने नियमों से परे जाकर यूपी में प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। समाजवादियों का कहना है कि इससे ही मंशा साफ होती है, लेकिन उन्हें तसल्ली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निरंतर सक्रियता से शीघ्र ही श्री आजम खान की रिहाई हो सकेगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तज़ीन फ़ातिमा जी के साथ मुलाकात के बाद कहा था कि हमारे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। डॉ. तज़ीन फ़ातिमा बीते दिसंबर महीने में जमानत मिलने के बाद रिहा होकर रामपुर पहुंची हैं। उसके तुरंत बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के रामपुर दौरे ने कुछ तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर भी विराम लगा दिया है।

उनके रामपुर दौरे की खास बात श्री आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर

यूनिवर्सिटी का मुआयना करना भी था। जहां प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर कोई भी आंच आएगी तो उसके लिए पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है। पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान साहब एवं उनके परिवार के साथ लगातार मजबूती से खड़ी है।

डॉ. तज़ीन फ़ातिमा ने भी अपनी रिहाई के बाद यही बात कही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ है और जो मदद पार्टी कर सकती थी, वो की गई। पार्टी को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। हमारे इरादे मजबूत हैं। जो लोग कमजोर पड़ रहे हैं या मायूस हैं उन्हें भी यह समझना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जैसे न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिला है, वैसे ही आजम खान साहब को भी इंसाफ मिलेगा। आजम खान साहब का अवाम के लिए

यह संदेश है कि जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत होनी चाहिए। आजम खान साहब और उनके परिवार के सदस्यों के साथ हो रहे बर्ताव पर उन्होंने कहा कि यह सब सियासी रंजिश है और पूरा देश जानता है कि यह ज़्यादाती है।



समाजवादियों की ट्रैक्टर रैली में गणतंत्र की झांकी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रध्वज लगाकर ध्वजारोहण किया। ट्रैक्टरों पर

समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगाया गया ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सैफई मैदान में हजारों किसानों और नौजवानों की उपस्थिति में ट्रैक्टर ट्राली के मंच से ध्वजारोहण करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी ।

हैरानी की बात यह रही कि गणतंत्र के पावन पर्व पर भी भाजपा सरकार का दमन जारी रहा । समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, झूठे मुकदमे लगाने से भाजपा सरकार बाज नहीं आई। राजधानी लखनऊ सहित अनेक जनपदों में भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाकर रास्ता रोका, कई नेताओं को घर से निकलने नहीं दिया और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने वालों पर दमन चक्र चलाया गया ।

श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा रोके जाने की कड़ी निंदा की । उन्होंने कहा कि भारत भाग्य विधाता के साथ समाजवादी खड़े हैं । भाजपा चाहे कितना अत्याचार कर ले, लेकिन समाजवादी बिना विचलित हुए उनका समर्थन करते रहेंगे

ट्रैक्टर रैली को रोके जाने की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक कर्वाइ के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आह्वान सफल रहा और प्रदेश के लाखों किसानों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा रोके जाने की कड़ी निंदा की । उन्होंने कहा कि भारत भाग्य विधाता के साथ समाजवादी खड़े हैं । भाजपा चाहे कितना अत्याचार कर ले, लेकिन समाजवादी बिना विचलित हुए उनका समर्थन करते रहेंगे ।

बलिया में नेता विरोधी दल श्री रामगोविन्द



चौधरी और पूर्व मंत्री श्री नारद राय के साथ जिलाध्यक्ष श्री राजमंगल यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली। सुल्तानपुर में लम्भुआ तहसील में श्री धर्मेन्द्र सिंह ने प्रदर्शन किया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी विधायक श्री नफीस अहमद ने बिलरिया गंज से महाराजगंज ब्लाक तक ट्रैक्टर रैली निकाली।

आजमगढ़ में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव, गाजीपुर की सिबराई तहसील में पूर्वमंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक श्री बीरेन्द्र यादव और रामधारी सिंह जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने रैली निकाली। कानपुर में डॉ॰ इमरान महानगर अध्यक्ष के साथ श्री इरफान सोलंकी एवं अमिताभ बाजपेई एमएलए ने ट्रैक्टर रैली निकाली।

गौतमबुद्ध नगर में जिलाध्यक्ष श्री वीरसेन यादव, अयोध्या सदर में श्रीमती लीलावती कुशवाहा, एमएलसी, बीकापुर तहसील में श्री अभय सिंह पूर्व विधायक, इटावा में श्री गोपाल यादव, मैनपुरी में श्री देवेन्द्र यादव, गोरखपुर में पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर यादव, जिलाध्यक्ष श्री रामनगीना साहनी एवं महानगर अध्यक्ष श्री जियाउल इस्लाम ने ट्रैक्टर रैली निकाली।

जौनपुर में विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री शैलेन्द्र यादव ललई, विधायक श्री लकी यादव, फिरोजाबाद में श्री दुर्गपाल सिंह यादव ने ट्रैक्टरों के साथ राष्ट्रध्वज फहराया।

सिद्धार्थनगर जनपद की इटावा तहसील पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकली। बिजनौर में श्री मनोज पारस और अयोध्या में पूर्व मंत्री श्री पवन पाण्डेय, पूर्व मंत्री श्री अवधेश प्रसाद, पूर्व विधायक जयशंकर पाण्डेय और झांसी में श्री चन्द्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर





हमारे सामने बड़ी लड़ाई है

- अखिलेश यादव

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 26 जनवरी 2021 को सैफई मैदान में हजारों किसानों और नौजवानों की उपस्थिति में ट्रैक्टर ट्राली के मंच से ध्वजारोहण करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पूर्व सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव एवं श्री तेज प्रताप सिंह यादव तथा एमएलसीगण श्री आनन्द भदौरिया, श्री सुनील सिंह साजन मौजूद थे।

श्री अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सामने बड़ी लड़ाई है। गणतंत्र दिवस पर संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेना है। भाजपा सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति करती है। नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार छीनने की साजिशें हो रही हैं। पूरे देश के किसान जाग गए हैं। समाजवादी भी खेती



किसानी से जुड़े हैं। देश को फौज पर गर्व है। अनेकता में एकता की अवधारणा ही राष्ट्रीय एकता की ताकत है। संविधान से देश चलना चाहिए।

सांसद एवं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान की आत्मा है। सत्ता पर आर्थिक ताकतों ने कब्जा कर रखा है। सत्ता दल देश की सम्पत्ति बेच रहा है। नए कृषि कानून से किसान का बेटा अपनी जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर होगा। भाजपाई व्यापारी हैं, वे लूट रहे हैं। भाजपाइयों से बचिए। उन्होंने कहा सन् 2022 में अखिलेश जी जिसे चुनाव लड़ाए उसे जरूर जिताना है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की मनमानी से किसानों के हित में निर्णय नहीं हुए हैं। राष्ट्र की सम्पत्ति पर कुछ लोगों का एकाधिकार कराने की साजिश है। उन्होंने किसानों के शांतिमय आंदोलन पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में है। अगर अन्नदाता आंतकवादी खालिस्तानी है तो उसका उपजाया अन्न भाजपाई क्यों खा रहे हैं? धान की लूट हो गई। किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिला।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर अन्याय के खिलाफ उतरा है। सरकार उनका दमन कर रही है। समाजवादी पार्टी संविधान और कानून को मानती है जबकि भाजपा नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है उन्हें अपमानित किया जा रहा है। किसान आंदोलन को रोकना भाजपा का दुष्कर्म है। आबादी के हिसाब से समाज के सभी तबकों को हक व सम्मान मिले, समाजवादी पार्टी इसके लिए

जनगणना की पक्षधर है।

श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा ओर रोजगार के मामलों में बहुत पीछे है। मुख्यमंत्री जी नौकरी का झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। 14-15 करोड़ को कहां रोजगार मिला है? निवेश में भी धोखा है। कोई निवेश नहीं आया। डिफेंस एक्सपो में प्रचार पर अरबों रुपए खर्च हुए उनके झूठे प्रचार की पोल खुल गई है। सबसे बड़ा 36 हजार करोड़ का एमओयू जिस कम्पनी ने किया था वह निरस्त हो गया है। भाजपा ढोंग करती है और जातिवाद फैलाती है। समाज में नफरत का ज़हर घोलती है। भाजपा का अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं है, जो भी काम हुए हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश की पहचान गंगा-जमुनी संस्कृति है। भाजपा इसे खत्म करना चाहती है। भाजपा डराकर राजनीति करती है। सड़क से प्रगति को रफ्तार मिलती है। उन्होंने देश की मजबूती और खुशहाली के लिए सभी से समाजवादी पार्टी का साथ देने और सन् 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और भाजपा को हटाने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा से सावधान रहना है क्योंकि यह चमत्कारी और चालाक पार्टी है।

रैली हुई। बाराबंकी में पूर्व मंत्री श्री अरविन्द सिंह गोप, विधायक सुरेश यादव, एमएलसी राजेश यादव, हरदोई में ऊषा वर्मा, रायबरेली में जिलाध्यक्ष इं. बीरेन्द्र यादव, पूर्व विधायक श्री रामलाल अकेला, एटा में जिलाध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह यादव, कुशीनगर पडरौना में पूर्णमासी देहाती पूर्व विधायक ने ट्रेक्टर रैली निकाली।

राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील में पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अशोक यादव एवं विधायक श्री अम्बरीष पुष्कर, अमर पाल सिंह ने ट्रेक्टर रैली निकाली और तहसील पर धरना देने के बाद ज्ञापन सौंपा। लखनऊ सदर तहसील में महानगर अध्यक्ष श्री सुशील दीक्षित के नेतृत्व में ट्रेक्टर रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विरोध में लखनऊ की सभी चारों तहसीलों पर प्रदर्शन हुए।

बख्शी का तालाब क्षेत्र में पूर्व विधायक गोमती यादव, विधानसभा अध्यक्ष श्री विदेश पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा अरविन्द गिरि तथा दिनेश सिंह, विशाल यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बस्ती में जिलाध्यक्ष श्री महेन्द्र यादव को ट्रेक्टर रैली निकालते समय गिरफ्तार कर लिया गया। फूलपुर इलाहाबाद में श्री रामवृक्ष यादव एमएलसी को बंदी बनाया गया। मेरठ में जिलाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह, विधायक श्री रफीक अंसारी आदि को सैकड़ों साथियों सहित हिरासत में लिया गया।

मलिहाबाद में श्रीमती सुशीला सरोज पूर्व सांसद, श्री इंदल रावत पूर्व विधायक, सी.एल. वर्मा राजबाला रावत, जयसिंह जयंत जिलाध्यक्ष लखनऊ और सरोजनीनगर में श्री अनुराग यादव, शिव शंकर सिंह उर्फ शंकर सिंह ने ट्रेक्टर रैली निकाली।

किसानों के साथ तहसील स्तर पर ट्रेक्टरों के



साथ जगह-जगह समाजवादी नेताओं ने ध्वजारोहण भी किया। फर्रुखाबाद में डॉ. राजपाल कश्यप एमएलसी ने स्कूल में ध्वजारोहण किया। बांगरमऊ, गंज मुरादाबाद ब्लाक के ब्लाक प्रमुख श्री विवेक सिंह पटेल ने रैली निकाली तो सी.ओ. व कोतवाल ने रोकटोक

26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रध्वज लगाकर ध्वजारोहण किया। ट्रैक्टरों पर समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगाया गया



की। कार्यकर्ताओं ने वहां धरना प्रदर्शन किया।

वाराणसी में सुश्री पूजा यादव, टाण्डा में श्री विशाल वर्मा, सहारनपुर में श्री जगपाल दास गुर्जर, कैसरगंज में श्री रामतेज यादव एवं अम्बेडकरनगर में श्री राममूर्ति वर्मा ने ट्रैक्टर रैली निकालकर ध्वजारोहण किया। जौनपुर में

मधुबाला पासी, संतकबीरनगर में संतोष यादव सनी, सीतापुर में राधेश्याम जायसवाल के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बांदा में बालकुमार पटेल, कुशीनगर में पूर्वमंत्री राधेश्याम सिंह, हापुड़ में तेजपाल प्रमुख, देवेन्द्र जाखड़, फकीरा चौधरी, राम करन निर्मल प्रदेश अध्यक्ष लोहिया

वाहिनी, अमरोहा में पूर्व मंत्री महबूब अली के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। मथुरा में जिलाध्यक्ष श्री लोकमणि जादौन, छाता में श्री प्रदीप चौधरी, गोवर्धन में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ राष्ट्रध्वज फहराया।

फोटो फीचर समाजवादियों की ट्रैक्टर रैली















महापंचायतों में दिख रही अन्नदाता की ताकत

समाजवादी किसान समिति लगातार सक्रिय

बुलेटिन ब्यूरो

केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सड़कों पर कीलें ठुकवा कर और खाई खोदकर किसान आंदोलन की धार को थाम लेने की कोशिश जरूर की लेकिन बुरी तरह नाकाम रही है। किसानों का आंदोलन लगातार और मजबूत होता जा रहा है। किसानों की महापंचायतों में लगातार जुट रही भारी भीड़ इसकी स्पष्ट पुष्टि कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर इन महापंचायतों को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं और गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि केन्द्र के नए कृषि कानूनों से कैसे कृषकों बड़ा नुकसान होगा। सपा के कार्यकर्ता किसान महापंचायतों की कामयाबी को भी अपनी पूरी सक्रियता से सुनिश्चित कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में 'समाजवादी किसान समिति' का गठन किया गया है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर मण्डलों के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

समाजवादी किसान समिति इस बात पर निगाह रख रही है कि कहीं किसानों के साथ अन्याय न

किसान धोखे का जवाब वोट से देंगे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान महंगाई और अपनी फसल का दाम न मिलने से दोहरी मार झेल रहा है। भाजपा इस मामले में पूर्णतया संवेदन शून्य है। किसान को उम्मीद थी उसको भाजपा नेताओं के वादों के अनुसार फसल की लागत का डयोढ़ा मूल्य मिल जाएगा और उसकी आय दोगुनी भी हो जायेगी। उसने भी सपना देखा था कि अब वह भी खुशहाल जिंदगी जिएगा, लेकिन धोखाबाजी की सरकार के मुखिया अधूरे वादों के साथ जनता के बीच असत्य बयानबाजी में व्यस्त हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 साल में गन्ने के दाम एक रुपया भी न बढ़ाने वाली भाजपा सरकार के चार दिन ही बचे हैं। किसान धोखे का जवाब अपने वोट से देंगे। चालू सीजन में भी गन्ने की सामान्य,

अगोती व अस्वीकृत प्रजाति का मूल्य क्रमशः 315,325 और 310 रूपए क्विंटल ही रहेगा।

गन्ना किसान कितनी बढहाली में जी रहा है इससे स्पष्ट है कि इस समय चीनी मिलों पर प्रतिदिन 2 करोड़ रुपया बकाया हो रहा है। 14 दिन के बाद किसान की अवशेष राशि बकाया श्रेणी में आ जाती है। अब तक प्रदेश में गन्ना किसानों का लगभग 10,174 करोड़ रुपये का बकाया हो चुका है। इसके साथ कानूनी तौर पर ब्याज देय होता है, जो नहीं दिया जा रहा है। परेशान गन्ना किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाता है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब 2012 में सरकार बनी थी तब शुरुआत में ही एक मुश्त गन्ने की राज्य परामर्श कीमत में 40 रुपये की वृद्धि की गई थी। समाजवादी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के साथ मुफ्त सिंचाई सुविधा

दी थी। किसानों के लिए पेंशन तथा फसल बीमा की भी व्यवस्था की गई थी। समाजवादी सरकार की कृषिपरक नीतियों को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्शील रही है। किसान यात्रा, समाजवादी किसान घेरा, ट्रैक्टर के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने हाल में किसानों के समर्थन में किए थे। आगे भी किसानों की हर मांग के साथ समाजवादी रहेंगे। ■



हो। सरकारी उत्पीड़न की कार्यवाहियों की यह समिति रिपोर्ट तैयार करेगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों को उनके हक एवं सम्मान से वंचित नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है।

समाजवादी किसान समिति में सर्वश्री स्वामी ओमवेश, कमाल अख्तर, संजय गर्ग, मेरठ के विधायक श्री रफीक अंसारी, छपरौली के श्री मनोज चौधरी और बड़ौत के श्री शोकिन्द्र तोमर, संजय लाठर, चंदन चौहान, अतुल प्रधान, आशु मलिक, नाहिद हसन, प्रोफेसर सुधीर पंवार, कर्नल सुभाष देशवाल आदि सदस्य नामित किए

गए हैं। यह समिति लगातार सक्रिय रहते हुए किसानों के बीच जन जागरण का काम कर रही है।

उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बाद से किसान आंदोलन और सघन होता चला जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में किसानों की बड़ी महापंचायतें हो रही हैं जिनमें जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। किसानों में भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ खासा गुस्सा है। ग्रामीणों ने अपने गांवों में भाजपा नेताओं के प्रवेश पर रोक की तख्तियां तक लगा दी हैं।

विदेशों तक में सरकार के किसान आंदोलन से निपटने के तौर-तरीकों की कड़ी निंदा होने लगी है।

महापंचायतों के दौरान ही किसानों ने छह फरवरी को चक्का जाम का आह्वान भी किया। उक्त कार्यक्रम को भी बड़ा जनसमर्थन हासिल हुआ। कई राज्यों में किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम को सफल बनाया जिससे भाजपा सरकार के इस प्रचार की भी हवा निकली कि किसानों का आंदोलन दरअसल कुछ ही राज्यों तक सीमित है। ■

अन्नदाता की राह में सरकारी कील-कांटे



रविकान्त



सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, लखनऊ विवि

"अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित ना करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए।"

-जॉन स्टुअर्ट मिल

दि

दिल्ली की सरहदों पर दो माह से अधिक समय से किसान आंदोलन चल रहा है। अब तक इसमें दो सौ से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किसानों की शहादत पर एक शब्द भी नहीं बोला है। राजनीतिक मंचों से लेकर संसद में भावुक होकर आंसू बहाने वाले नरेंद्र मोदी के लिए लगता है, किसानों की पीड़ा और उनकी शहादत का कोई मोल नहीं है।

अलबत्ता, इसके उलट उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए आंदोलनकारी किसानों के लिए आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे लांछित शब्दों का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री की निष्ठुरता और उनके द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्दों से किसान बेहत आहत और नाराज हैं। सोशल मीडिया से लेकर सामान्य

चर्चाओं में भी नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य की तीखी आलोचना हो रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को एक आशंका व्यक्त की थी। उनका कहना था कि आने वाले दौर में संभव है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम न करे। आज नरेंद्र मोदी पर अपने चुनिंदा कारपोरेट मित्रों पर मेहरबान होने के आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन के प्रति इतने निष्ठुर और संवेदनहीन इसलिए हैं क्योंकि पहली बार आंदोलनकारी, उनके उद्योगपति मित्रों- अंबानी और अडानी का खुलकर नाम ले रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कारपोरेट मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी के कारपोरेट मित्रों की तीखी आलोचना की है। अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के

बहिष्कार की मुहिम चलाई गई। संभवतया इसी वजह से ही नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आंदोलनकारियों को परजीवी कहकर अपमानित किया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की एक और साजिश रची जा रही है? दिल्ली की सरहदों पर लाखों किसान फिर से आ डटे हैं, लेकिन मोदी सरकार का दमन जारी रहा है। आंदोलन को रोकने के लिए और किसानों को डराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर कटीले तार बिछाए। नुकीली छड़ें लगाईं। सड़क पर आरसीसी की स्थाई बैरिकेडिंग लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल इन भयावह तस्वीरों की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस से लेकर स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा



थनबर्ग जैसी अनेक अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने किसानों के समर्थन में दृष्टि किए। आलोचनाओं से चौतरफा घिरी भाजपा सरकार ने देशभक्ति और संप्रभुता के नाम पर विदेशी हस्तियों के दृष्टि को डिस्क्रेडिट करने के लिए सुनियोजित कैम्पेन चलाया। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट और संगीत के सितारों को विदेशी हस्तियों के खिलाफ उतारा गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के प्रति हमदर्दी और उनसे संवाद करने के बजाय उन्हें परजीवी कहकर अपमानित किया है। संविधान का अनुच्छेद 19, भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति और आंदोलन करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन मोदी सरकार विरोध की प्रत्येक आवाज को कुचलने पर आमादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों- मजदूरों द्वारा चुनी

संविधान का अनुच्छेद 19, भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति और आंदोलन करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन मोदी सरकार विरोध की प्रत्येक आवाज को कुचलने पर आमादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों- मजदूरों द्वारा चुनी हुई सरकार क्या कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है?

हुई सरकार क्या कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है? भाजपा सरकार का मनमाना रवैया लगातार जारी है। क्या न्यू इंडिया में लोगों को विरोध और आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है? जेएनयू के छात्र आंदोलन से लेकर नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन को जिस तरह बदनाम करके बर्बरतापूर्वक कुचल दिया, क्या सरकार इसी तरह किसान आंदोलन को भी खत्म करना चाहती है?

करीब 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में लाखों लोगों की कुर्बानियों और सालों की जेलों की प्रताड़ना के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिली। स्वाधीनता आंदोलन और संविधान सभा के गहन चिंतन मनन की प्रक्रिया में हमने लोकतंत्र को अर्जित किया। आजादी के



बाद भूदान आंदोलन, जेपी आंदोलन सहित अनेक मजदूरों, किसानों, औरतों और दलित-पिछड़ों के आंदोलनों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत के लोगों का मतलब सिर्फ वोटर होना नहीं है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा विपक्ष जनता होती है। सरकार के कामकाज पर जनता की राय और उसकी आलोचना के अपने मायने होते हैं। आंदोलन जनता के जीवित और विवेकशील होने के परिचायक होते हैं। इसीलिए समाजवादी चिंतक डा. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें पाँच साल का इंतजार नहीं करतीं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए होता है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करके मोदी सरकार अर्जित लोकतंत्र को 'लंगड़ा' कर रही है। लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। मीडिया संस्थान सरकार के भोंपू बन गए हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने व्यापारियों, मध्य वर्ग और गरीबों को आर्थिक

रूप से बदहाल कर दिया है। ऐसे अलोकतांत्रिक और एकतरफा फैसलों से भारत के लोकतंत्र की छवि खराब हुई है। डेमोक्रेसी इन सिकनैस एंड हेल्थ नामक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2019 के मुकाबले भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में दो अंक नीचे फिसलकर 51 से 53 वें स्थान पर आ गया है। यह फिसलन बहुत थोड़ी लगती है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इस इंडेक्स में भारत के लोकतंत्र का पतन दोगुना हुआ है। 2014 में 7.29 अंकों के साथ भारत 27 वें स्थान पर था। 2020 में 6.61 अंकों के साथ 53 वें स्थान पर पहुँच गया है। रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्व को शामिल किया है। विश्लेषक कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष आधार कमजोर हुआ है। कोरोना महामारी से निपटने के तरीके से नागरिक अधिकारों का दमन हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा कि अचानक लाकडाउन लगाने के कारण करोड़ों प्रवासी मजदूर सैकड़ों कोस पैदल चलने के लिए मजबूर

हुए। सैकड़ों औरतें, बूढ़े, बच्चे रास्ते में भूख प्यास से मर गए। इसी तरह 2019 में धारा 370 खत्म करके मोदी सरकार ने कश्मीर को लगभग जेल में तब्दील कर दिया। नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार किसानों के आंदोलन का बर्बरतापूर्वक दमन कर रही है। यह आंदोलन किसानों के अधिकारों का तो है ही, लोकतंत्र की बहाली का भी आंदोलन है। इसलिए जनता और विपक्ष को भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के फासीवादी रवैये का मुकाबला करना होगा।

फोटो सौजन्य - गूगल

नाम बड़े और दर्शन छोटे

अरविन्द मोहन



लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

यह हैरानी की बात नहीं है कि जिस दिन 'शताब्दी में खास बजट' कहकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहली फरवरी को जो धन विधेयक प्रस्तुत किया उसी दिन दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए मोटी कीलों, गड्डे और बैरियर समेत आठ लेयर वाली 'सुरक्षा व्यवस्था' की गई। यह बात उस दिन दब गई, पर चुभने वाली यह व्यवस्था खुद जब सरकार को ज्यादा परेशान करने लगी तब कीलों को हटाया गया,

लेकिन बजट की उससे भी ज्यादा चुभने वाली चीजों पर अभी तक चर्चा भी नहीं हो रही है।

बजट में भी किसी किस्म के गरीब समर्थक, किसान समर्थक, महिला समर्थक और गांव समर्थक दिखावे की भी जरूरत नहीं दिखी। उसमें सबसे बड़ी रियायत के नाम पर 75 पार के बुजुर्गों को, अगर उनकी एक रुपए की भी आमदनी नहीं होती और उन्होंने सरकार द्वारा तय बैंकों में ही अपने खाते रखे हैं तब, आयकर का रिटर्न भरने से छूट ही है। या फिर सोना-चाँदी पांच फीसदी सस्ता होना (अगर आपमें पचास हजार प्रति दस ग्राम सोना खरीदने की क्षमता बची हो) है।

वरना लगभग अस्सी लाख गाड़ियों को स्क्रेप में बेचने, पूरे बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के हवाले करने, दो सरकारी बैंकों को बेचने, बैंकों के सारे एनपीए और डूबे कर्ज को एक प्राधिकार के हवाले करके उनको सारी जबाबदेही से मुक्त करने और सैनिक स्कूल तक को विदेशी निवेशकों के हवाले करने, सरकारी परिसम्पत्तियों को बेचकर मोटी रकम जुटाने, शेयर बाजार की कमाई को हर बाधा-बंधन से मुक्त करने और चुनाव वाले राज्यों के लिए भाजपा को लाभ देने वाली घोषणाओं की बेशर्मी में कोई झिझक नहीं दिखाई गई है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की हालिया सिफारिशों को दरकिनार करते हुए केन्द्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से का लगभग ग्यारह फीसदी पैसा न देना और पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क घटाकर उसी रकम को उपकर के रूप में अपनी जेब में डालने की राजनैतिक तानाशाही भी दिखाई गई है। शिक्षा के निजीकरण, मनरेगा और किसान आन्दोलन के दौर में भी खेती के बजट को घटाने का दुस्साहस भी निर्मला सीतारमन ने किया। सब से खास यह हुआ है कि जिस कोरोना काल में अर्थव्यवस्था सबसे खस्ताहाल रही, आमदनी

और खर्च में तकरीबन दस फीसदी का फासला रह गया (यह सरकारी अनुमान है। अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री घाटा पन्द्रह फीसदी तक मानते

अभी तक किसी भी सरकार ने गरीबों से बेपरवाही और अमीरों तथा कारपोरेट जगत से यारी दिखाने में ऐसा दुस्साहस नहीं किया था जितना इस बजट में हुआ है। मध्यमवर्ग और गरीबों के लिए एक भी लाभ घोषित नहीं हुआ है



हैं), उसमें भी सड़क समेत कथित संरचना क्षेत्र में भारी निवेश की योजनाओं की घोषणा के साथ

रिकार्ड 6.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान भी वित्त मंत्री ने बता दिया। अब लोग चाहे जो कहें, सरकार और भाजपा के लोग ही नहीं, शेयर बाजार कुलांचे मार रहा है। इस घाटे

का मुद्रास्फ़ीति पर क्या असर होगा इसकी चर्चा भी सिरे से गायब है।

शेयर बाजार तो कोरोना से पस्त हालातों के बीच भी उछलता रहा है और सेंसेक्स पचास हजार के आंकड़े तक पहले ही पहुंच गया था। पिछले दो महीनों में बाजार का पूंजीकरण करीब दस लाख करोड़ बढ़ने और अर्थव्यवस्था की रफ्तार से इस कमाई का मेल न खाने के आधार पर शेयर बाजार की कमाई पर कर लगाने, नाजायज पैसे को बाजार में लाने का मुख्य स्रोत, पी-नोट्स पर किसी तरह का अंकुश लगाने और किसान आन्दोलन के दबाव में उनके हक में या कोरोना के चलते आम लोगों को राहत देने वाले फ़ैसलों का दबाव होने की बात से बाजार कुछ सहमा था।

अमीरों पर कोरोना टैक्स और शेयर बाजार की बेहिजाब कमाई पर कुछ कर लेने की चर्चा काफी समय से हवा में थी, लेकिन जैसे ही निर्मला जी ने बिना झिझक कारपोरेट क्षेत्र के पक्ष में फ़ैसलों की झड़ी लगाई, पी-नोट्स पर जुबान भी न खोली, नए कर लगाने की कौन कहे डिवेडेंट पर कर लगाने की व्यवस्था में भी ढील देने, कैपिटल गेन में लाभ देने जैसे घोषणाएं करनी शुरू कीं, बाजार उछलने लगा और उसका उछलना अभी तक जारी है क्योंकि बजट के प्रावधानों का मतलब समझते जाने के साथ अमीर और पूंजी वाले जमात का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है।

अभी तक किसी भी सरकार ने गरीबों से बेपरवाही और अमीरों तथा कारपोरेट जगत से यारी दिखाने में ऐसा दुस्साहस नहीं किया था जितना इस बजट में हुआ है। मध्यमवर्ग और गरीबों के लिए एक भी लाभ घोषित नहीं हुआ है। सबसे डरावना यह फैसला है कि स्कूली शिक्षा का बजट पांच हजार करोड़ रुपए घटा दिया गया और पिछले साल विदेशी विश्वविद्यालयों को आने की इजाजत देने के बाद इस बार सैनिक

केन्द्र का बजट मायूसी का दस्तावेज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि केन्द्र सरकार का बजट नहीं, मायूसी का दस्तावेज है। बजट में मिले धोखे को किसान-नौजवान, छोटा कारोबारी, नौकरी पेशा कोई भी भूल नहीं पाएगा। चुनाव से पहले भाजपा ने जुमले और सपने बेचे, सरकार बनने के बाद अब वह जमीन से लेकर जमीर तक बेचने पर आमादा हो गई है।

भाजपा सरकार में लोगों के लिए अच्छा कुछ भी नहीं है। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी बजट में माइक्रोस्कोप लगाकर भी किसी के लिए अच्छे दिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त सेस, यूरिया सब्सिडी और पोषण आधारित सामग्री पर सब्सिडी आवंटन में भारी कटौती कृषि विनाशक नीतियों का परिचायक है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है राजनीतिक दल के रूप में भाजपा का रूपांतरण ट्रेडिंग कम्पनी के रूप में हो गया है। उसका

काम विपक्षी विधायकों की खरीद फरोख्त और राष्ट्रीय संपत्तियों को चंदघरानों को देकर रकम एकत्र करना रह गया है। भाजपा सरकार की तमाम घोषणाएं सिर्फ रोकड़ा बटोरने की कोशिश साबित होंगी। वित्तमंत्री जी ने अपना बजट भाषण इस बार टैबलेट से पढ़ा था। आखिर किसान उनके टैबलेट का क्या करेंगे, उसे ओढ़ेंगे या बिछाएंगे? कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए मात्र 2.02 प्रतिशत आवंटन बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनके दिल में है किसान-गांव। इससे बड़ा किसानों का क्या उपहास होगा?

रोजगार सृजन की कई कहानियां भाजपा सरकार सुनाती रहती है लेकिन हकीकत यह है कि मनरेगा के मद में आवंटन 30 प्रतिशत कम कर दिया गया है। ग्रामीण परिवारों पर इससे बड़ा दबाव बढ़ेगा। इस बजट में किसी सुधार की शुरुआत नहीं की गई है। सीमा शुल्क, जीएसटी कानून का ढांचा पूरी तरह अतार्किक है। भारत सरकार उन राज्यों को झांसे में लेना चाहती है जहां चुनाव होने हैं। जहां चुनाव नहीं

स्कूल, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र के स्कूलों को निजी भागीदारी में सौंपने का फैसला हो गया। अगर इस बजट में एक उल्लेख की बात है तो स्वास्थ्य का बजट दो गुने से भी ज्यादा होना, लेकिन गौर से देखने पर लगेगा कि इसका भी बड़ा हिस्सा पानी की आपूर्ति, स्वच्छता मिशन भाग दो और कोरोना के टीकाकरण का है।

बदहाल स्वास्थ्य सेवा और अस्पतालों पर निवेश दिखावटी ही है। अगर देश भर में टीकाकरण के खर्च के अनुमान और बजट के भारी प्रावधान को देखें तो साफ लगता है कि देश भर के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका नहीं मिलने जा रहा है। यह

अगर देश भर में टीकाकरण के खर्च के अनुमान और बजट के भारी प्रावधान को देखें तो साफ लगता है कि देश भर के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका नहीं मिलने जा रहा है

अनुमान है कि सबको टीका देने पर एक लाख करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है जबकि बजट में चालीस हजार करोड़ भी नहीं रखे गए हैं। इसका मतलब तो यही होगा कि यह चुने हुए समूहों और इलाकों में दिया जाएगा या फिर राज्यों को अपने खर्च पर अभियान चलाना होगा।

यही नहीं इस कोरोना के आफतकाल में, जो मनरेगा बेरोजगार गरीब लोगों (कम से कम इस योजना में कोई अमीर या पैसे वाला बेरोजगार काम नहीं कर रहा होगा) का सहारा बना और जिस पर सरकार ने उचित ही आवंटन राशि बढ़ाई थी, उसे महा बेरोजगारी वाले इस दौर में

होने हैं उनकी उपेक्षा कर दी गई है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार सृजन और युवाओं को काम देने की दिशा में यह बजट निराशा के संकेत देता है। युवाओं को विवेकानंद जी का पाठ पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी नौजवानों के हाथों में नई नियुक्तियों के पत्र भी नहीं थमा रहे हैं। किसानों के बारे में भी बड़ी बातें की गईं लेकिन यह बात भुला दी गई कि मंहगाई 31 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि किसान के लिए समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना रकम अदा करने का दावा हवाई साबित हो जाता है।

बजट में कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को कोई खास रियायत नहीं मिली है। मध्यम वर्ग को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि सामान्य चीजों के दामों में बाजार में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है। भाजपा से अब लोगों का भरोसा टूट गया है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में

जनता उसे सचमुच 'अच्छे दिन' दिखाएगी जब भाजपा सत्ता से बाहर खुले वातावरण में सांस लेने का सुख हासिल करेगी।



इस बार कम कर दिया गया है। यह सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, लेकिन यह कब तक होगा और कितना लाभकर होगा, यह पूरी तरह अनिश्चित है।

ऊपर से इस सरकार का रिकार्ड ऐसा है कि घोषित योजनाओं पर काम हो यह भरोसा करना भी

मुश्किल है। बेचारे बेरोजगार लोग क्या इतना इंतजार कर सकते हैं? अगर काम का बोझ बढ़ने और वेतन कटौती वाले हिसाब को भूल भी जाएं तो करीब डेढ़ करोड़ लोग कोरोना से बेरोजगार

कोरोना ने पर्यटन, होटल, विमानन ही नहीं, पहले से बदहाल रियल इस्टेट उद्योग की कमर तोड़ दी है और सरकार ने इसमें कर राहत का मामूली पुराना पैकेज एक साल और बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है

हुए हैं। मुश्किल यह है कि वापस रोजगार पाने या नया काम करने के मामले में पुरुष और महिलाओं के बीच तीन गुने का फासला है। ऐसा ही अंतर शहरी और ग्रामीण रोजगार के मामले में भी है। सिर्फ इन लोगों को ही नहीं, अर्थव्यवस्था के कई कमजोर पड़े क्षेत्रों को तत्काल मदद की जरूरत है। बीरबल की खिचड़ी पकाने की नहीं। कोरोना ने पर्यटन, होटल, विमानन ही नहीं, पहले से बदहाल रियल इस्टेट उद्योग की कमर तोड़ दी है और सरकार ने इसमें कर राहत का मामूली पुराना पैकेज एक साल और बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है।



अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो लाख से ज्यादा आवासीय इकाइयां बिन बिकी खड़ी हैं। पर्यटन और होटल व्यवसाय तो साल भर से पस्त पड़ा है और सबसे ज्यादा बेकारी यहीं हुई है। अब विदेशी मेहमानों की आवाजाही या अपना धार्मिक पर्यटन जब तक सामान्य स्थिति में नहीं लौटता, तब तक तो अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में लगे लोगों और पूंजी को मदद की जरूरत है ही। कई उद्योगों पर भी बहुत बुरी मार पड़ी है और कई का बदलाव सदा के लिए हो चुका है। वर्क फ्राम होम की संस्कृति भले कोरोना काल की मजबूरी हो, पर यह अब टिकेगा ही, पर इस जैसे बदलावों की न तो बजट में चर्चा है न इनके बारे में कोई फैसला लिया गया है।

पर जो मुश्किल समझ से परे है वह किसानों और खेती की उपेक्षा का है जो आंदोलित भी हैं और

मेक इन इंडिया से लेकर स्मार्ट सिटी तक की योजनाओं का जो हाल हुआ है वह भरोसा नहीं देता कि यह सरकार सचमुच कुछ ठोस आर्थिक काम कर सकती है। इसका काम सिर्फ हवाबाजी और अपने लोगों की तिजोरी भरना है



चुकी है।

संरचना क्षेत्र में करीब साढ़े पांच लाख करोड़ के पूंजीगत निवेश का प्रस्ताव थोड़ा आकर्षक लगता है पर रोजगार के हिसाब से या आम आदमी की आर्थिक गतिविधियों को गति देने के हिसाब से शून्य है, क्योंकि सारी योजनाएं बरसों बरस में पूरी होंगी और रोजगार का कोई ठोस भरोसा नहीं देती। बाजार इसी पर लट्टू होकर नाच रहा है लेकिन मेक इन इंडिया से लेकर स्मार्ट सिटी तक की योजनाओं का जो हाल हुआ है वह भरोसा नहीं देता कि यह सरकार सचमुच कुछ ठोस आर्थिक काम कर सकती है। इसका काम सिर्फ हवाबाजी और अपने लोगों की तिजोरी भरना है। जिस राष्ट्रवाद के नाम पर वह अब तक चुनाव जीतती थी इस बजट में 'रक्षा' शब्द सिर्फ एक बार आया और हर बार बजट प्रावधान जितना खर्च नहीं होता।

हां, सरकार वोट बटोरू मुफ्त राशन, मुफ्त गैस और संसाधनों के चुनावी इस्तेमाल को बढ़ाती लगती है। लगभग एक करोड़ नए घरों तक गैस पहुंचाने की घोषणा हुई जो मुख्यतः चुनाव वाले प्रदेशों में बंटेगा। पहले बंटे सिलेंडर का कितना उपयोग हो रहा है और उसके लिए मिलने वाले गैस की सबसिडी कैसे खत्म कर दी गई है इसका कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ तीन काम हुए लगते हैं- वोट दिलाऊ खर्च, अपने दुलारे कारपोरेट वर्ग के लिए भारी भरकम लाभ की योजनाएं और अपनी सहूलियत और शान का खर्च।

कोरोना का असर न संसद के लिए बनती नई इमारत के खर्च पर पड़ा है न प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों के नए आवास पर और न शान के लिए खरीदे गए दो विशेष विमानों पर। किसानों को दिल्ली से दूर रखने पर कितना खर्च हो रहा है उसका हिसाब तो देना भी न था और आश्चर्य नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के सस्ता

होने का लाभ ग्राहकों को न देकर मोदी सरकार ने सात साल में जो करीब तेरह-चौदह लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, लगभग उतनी ही रकम मुफ्त राशन और मुफ्त गैस बांटने जैसी योजनाओं पर खर्च किया है।

इस बार ज्यादा अखरने वाली बात यह है कि तंगी और मुश्किल की स्थिति में लगभग इतनी ही रकम का राजकोषीय घाटा छोड़कर पांच लाख करोड़ के अनिश्चित निवेश के आधार पर नगाड़ा बजाया जा रहा है और किसी गरीब, बेरोगजार और किसान को एक भी रुपए का सीधा लाभ नहीं दिया गया है, जबकि कोरोना ने सबकी हालत पस्त की है और सरकारी लाकडाउन ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

फोटो सौजन्य - गुगल



जिन्होंने कोरोना काल में देश को सहारा दिया है। आर्थिक विकास की दर अभी तक जब भी ऋणात्मक होती थी तो खेती खराब होने या सूखा के चलते हुई थी। यह पहला मौका है जब खेतिहर लोग सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज देने के लिए मारामारी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने ही बताया कि सरकार चालू बजट में भी खेती के लिए तय रकम खर्च नहीं कर सकी थी और इस बार उसने बजट कम कर दिया है। इस बीच डीजल का दाम बेहिसाब बढ़ाने, बिजली का रेट बढ़ाने, युरिया की बोरी का वजन कम करना और दाम बढ़ाने से लेकर काफी ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। गन्ने का दाम कई साल से नहीं बढ़ा है और बार-बार झूठ बोलने के बावजूद अभी तक उनका बकाया भुगतान भी नहीं हुआ है। किसानों को लागत का डेढ़ गुना देने का वादा तो सरकार अब भूल ही

समाजवादियों ने सादगी से मनाया डिम्पल जी का जन्मदिन



बुलेटिन ब्यूरो

महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और कन्नौज से पूर्व सांसद श्रीमती डिम्पल यादव का जन्मदिन 15 जनवरी 2021 को समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में सादगी के साथ उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया।

बढ़ी संख्या में आई महिलाओं, पार्टी नेताओं तथा संत समाज के लोगों ने श्रीमती डिम्पल यादव को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य





डिम्पल जी की प्रेरणा से ही समाजवादी सरकार में वुमन पावर लाइन 1090 स्थापित हुई थी

तथा जीवन में सफलता एवं यशस्वी होने की शुभकामनाएं दी।

केक काट कर तथा गरीबों को कम्बल-वस्त्र तथा फल-भोजन बांट कर श्रीमती डिम्पल यादव के दीर्घ जीवन की कामना की गई। कन्नौज से आए पृथ्वीनाथ सपेरा ने बीन की धुन से अभिनंदन किया तो कई लोगों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की विशिष्ट उपस्थिति रही।

लखनऊ और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी डिम्पल जी के जन्मदिन पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। खासतौर पर इस बात का स्मरण किया गया कि डिम्पल जी की प्रेरणा से ही समाजवादी सरकार में वुमन पावर लाइन 1090 स्थापित हुई थी। महिलाओं के बीच डिम्पल जी की लोकप्रियता की मिसाल कायम हुई है।

सुश्री पूजा यादव, महानगर अध्यक्ष महिला सभा वाराणसी, ने श्रीमती डिम्पल यादव जी को बाबा काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद, चंदन व मां अन्नपूर्णा की चुन्नी, उनका धान एवं पशमीना का अंगवस्त्र भेंट किया। श्री अखिलेश यादव को उन्होंने रुद्राक्ष की माला भेंट की। महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अपर्णा जैन एवं डॉ. नीतेन्द्र सिंह यादव कानपुर ने गरीबों के लिए दो दर्जन साइकिलें भेंट की। कानपुर के महंत हरिओम शुक्ला जी उर्फ हरिदास महाराज जी ने भी आशीर्वाद देते हुए डिम्पल जी को जीवन में असीम सफलता की शुभ कामना की।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमें 351 सीटें जीतने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके लिए बूथ स्तर पर पूरी मुस्तैदी से जुटना होगा। श्री अखिलेश यादव



22 में बाइसिकल





को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होगी। भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना है। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चियों के लिए भाजपा राज सर्वाधिक निराशापूर्ण रहा है। इनके साथ दुष्कर्म की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है।







बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी आंदोलन में छोटे लोहिया का बड़ा योगदान

समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता छोटे लोहिया श्री जनेश्वर मिश्र की 11वीं पुण्यतिथि पर 22 जनवरी 2021 को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में समाजवादी पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व एवं समाजवादी आंदोलन में उनकी भूमिका पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बरेली में

पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में जनेश्वर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया।

लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम श्री जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमतीनगर लखनऊ में हुआ। समाजवादी पार्टी मुख्यालय एवं जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय में भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

श्री जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा पर सर्वश्री अहमद हसन नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद,

राजेन्द्र चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री, नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, नारद राय पूर्व मंत्री, अरविन्द कुमार सिंह, उदयवीर सिंह, राजेश यादव, लीलावती कुशवाहा, जगजीवन प्रसाद सभी एमएलसी, अरूण वर्मा, एवं सनातन पाण्डेय पूर्व विधायक ने माल्यार्पण करके श्री मिश्र जी को श्रद्धांजलि दी।

नेताजी ने साहस और बलिदान की नई शौर्यगाथा लिखी



भारत भूमि के राष्ट्र नायक एवं स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी 2021 को समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने नेता जी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस की गिनती भारत के वीर सपूतों में की

जाती है। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार बनाकर उन्होंने अपने अदम्य साहस और बलिदान से विश्व में नई शौर्यगाथा लिख दी थी। सुभाष बाबू पूर्ण स्वराज्य के पक्षधर थे। भारत को महाशक्ति के रूप में देखना उनका सपना था।

श्री यादव ने कहा कि नेता जी में राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना थी। उनके नेतृत्व में बलिदानियों की ऐसी टोली बनी थी जिनमें जाति, धर्म क्षेत्र की कोई भावना नहीं थी। उनके जयहिंद के नारे की गूंज से ब्रिटिश साम्राज्य दहल उठा था। नौजवानों

के वे प्रेरणास्रोत थे। उनके नाम से ही लोगो में आज भी नए जोश का संचार हो जाता है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल मौजूद थे।



सादगी की मिसाल थे जननायक कर्पूरी



समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में 24 जनवरी 2021 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रखर समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनका श्रद्धापूर्ण स्मरण किया गया। लखनऊ महानगर स्थित एच पार्क में कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का मानना है कि श्री कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति में भी सेवा भावना को प्रमुखता दी थी। वह सदा गरीबों के लिए लड़ते रहे। वह दो बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार विधायक

रहे किन्तु उनका जीवन बेदाग रहा। अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए वे जाने जाते थे। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं।

श्री अखिलेश यादव ने हमेशा कहा है कि समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय की अवधारणा के समर्थन में जातीय जनगणना की मांग की है। इससे जनसंख्या के अनुपात में सभी को अधिकार और सम्मान मिल सकेगा। भाजपा आरक्षण के साथ साजिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 17 जातियों को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का प्रयास किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों, दलितों तथा समाज के कमजोर वर्ग के

लोगों को प्राथमिकता के आधार पर तमाम सुविधाएं दी गई थीं।

जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी तथा पूर्व मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह, विधान परिषद सदस्य अरविन्द कुमार सिंह, पूर्व विधायक इन्द्राणी वर्मा, विनोद सविता एवं संजय विद्यार्थी सविता ने श्री कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की।



पूर्वांचल के बहादुर नेता थे पारसनाथ

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 12 जनवरी 2021 को जौनपुर जनपद के श्रीराम पीजी कालेज आदमपुर निगोह पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय पारसनाथ यादव के जयंती समारोह में शामिल होने के बाद उनके चित्र पर माल्यापर्ण कर श्रद्धांजलि दी।

जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय पारसनाथ यादव सपा के संस्थापक दल के सदस्य और



पूर्वांचल के कद्दावर, बहादुर व साहसी नेता थे।

जौनपुर पहुंचने से पहले श्री अखिलेश यादव वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे और फिर सड़क मार्ग से जौनपुर निकल गए। वाराणसी से जौनपुर के रास्ते में कई जगह आम लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने श्री अखिलेश यादव का जबरदस्त स्वागत किया। जौनपुर में उनकी सभा में भी बड़ी भीड़ जुटी।

आदमपुर निगोह स्थित श्रीराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वर्गीय पारसनाथ यादव के जयंती समारोह में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व मंत्री स्व.पारसनाथ यादव को सपा के कद्दावर नेता की संज्ञा देते हुए कहा कि पारसनाथ बहादुर और साहसी नेता थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर सपा को मजबूत करें।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के दौरान लकी यादव ने कहा की आप प्रचार में आ जाइए। मैंने कहा कि मुझे मत बुलाओ। पता किया तो मालूम पड़ा कि बीजेपी लड़ाई में है ही नहीं। मैंने लोगों से उसी समय कह दिया था कि बहादुर बाप का लकी बहादुर बेटा है जीत के आएगा और वह जीत कर आया। श्री अखिलेश यादव ने लोगों से 2022 के चुनाव में सपा का परचम लहराने का आह्वान किया।

इसके पूर्व उन्होंने स्वर्गीय पारसनाथ यादव के स्वजनों से मिलकर दुख प्रकट करते हुए करीब दस मिनट तक परिवार के साथ रहकर हाल चाल जाना। इसके साथ ही पारसनाथ व उनकी पत्नी हीरावती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद वह मंच पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट व जयकारों से स्वागत किया।






साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav 

@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)



Akhilesh Yadav 

@yadavakhilesh

आज जिस तरह छल-बल का प्रयोग कर भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन को कुचल रही है, उससे किसानों के साथ-साथ हर सच्चे भारतीय की आत्मा रो रही है। किसान अगले चुनाव में सरकार की क्रूरता का जवाब वोट से देंगे।

आज भाजपा जिन किसानों को सड़क से उठा रही है, वो कल भाजपा को ही सड़क पर ले आएंगे।



Akhilesh Yadav 

@yadavakhilesh

आंदोलनों से स्वतंत्रता पाने वाले देश में आंदोलनरत किसानों-नागरिकों को 'आंदोलनजीवी' जैसे आपत्तिजनक शब्द से संबोधित करना हमारे देश के क्रांतिकारियों एवं शहीदों का अपमान है। आज़ादी के आंदोलन में दोलन करने वाले आंदोलन का अर्थ क्या जाने।

भाजपा शहीद स्मारक पर जाकर माफ़ी माँगे!



Akhilesh Yadav 

@yadavakhilesh


जय जिनेंद्र!

जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ जी के जन्म, तप एवं केवलज्ञान प्राप्ति के कल्याणक क्षेत्र काम्पिल्य में आने के सौभाग्यशाली क्षण।

उप्र सर्वधर्मसंभाव की अनुपम धरती है।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav 

@yadavakhilesh

सियासत तू है कमाल
उठाके रास्ते में दीवार
बिछाकर कँटीले तार
कहती है आ करें बात

[#किसान](#)

[#नहीं_चाहिए_भाजपा](#)



Following

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

किसान आंदोलन में शहादत देने वाले उप्र की पीलीभीत के स्व. बलजिंदर जी व रामपुर के स्व. नवरीत सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि!
सरकार शहीदों के आश्रितों को मुआवज़ा दे।

सरकार में आने पर सपा किसान आंदोलन के शहीदों की याद में स्मारक बनवाएगी व किसान सम्मान पुरस्कार की भी घोषणा करेगी।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

भाई अभी भी सबसे प्रसिद्ध अमरूद 'इलाहाबादी अमरूद' कहलाता है या उसका भी नाम बदलकर 'प्रयागराजी अमरूद' हो गया है?

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

प्रयागराज में भाजपा सरकार ने निषाद समाज की नावें तोड़कर उनके पेट पर लात मारी है।
भाजपा सरकार तत्काल निषाद समाज से माफ़ी माँगे और रोज़गार के लिए नयी नावें दे।

उप्र सरकार ने डायल 100 जैसी सुविधाएं निष्क्रिय कर दी हैं व ठोको नीति के तहत अब गरीबों तक को निशाना बनाया जा रहा है।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

पार्टी कार्यालय में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

नई हवा है नई सपा है
बड़ों का हाथ युवा का साथ ..

[Translate Tweet](#)





किसान मज़दूर के हक़ की बात
सपा है आगे सपा है साथ